

MESSAGES FROM LOK SABHA.... (Contd.)**The Right to Information Bill, 2005**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary General of Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Right to Information Bill, 2005, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 2005."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

HALF AN HOUR DISCUSSION

**Points arising out of the Answer given in the Rajya Sabha on
the 2nd May, 2005, to Starred Question No. 524 regarding
'Promotion of Urdu Language in Bihar*.**

श्री शाहिद सिद्धिका (उत्तर प्रदेश) : डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमें उर्दू पर बात कहने का मौका दिया, क्योंकि किसी हाऊस में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि उर्दू पर बात हो 155 सालों से उर्दू का जो दर्द है, मैं उसे यहां बयान नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लम्घी दास्तान है, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए। मैं आज जो बात करूंगा, उसमें बिहार में उर्दू की भी बात करूंगा, लेकिन बिहार में जो उर्दू है, वह आइसोलेशन में नहीं है। आप सिफ बिहार में उर्दू को जिन्दा नहीं रखे सकते, अगर पूरे हिन्दुस्तान में उर्दू का कल्प होगा। अगर बिहार में उर्दू को जिन्दा रखना है तो रोगजार से उसे जोड़ना होगा, पूरे हिन्दुस्तान में उर्दू को उसका हक देना होगा महोदया, इसलिए मैं पूरे हिन्दुस्तान के मसले के सामने रखते हुए बिहार की बात करूंगा। जी पिछली बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा आज की बात करता हूँ कि जो कॉमन मिनियम प्रोग्राम बना, उसमें वारा किया गया कि उर्दू को उसका हक दिया जाएगा, जहां पर 10 फीसदी से ज्यादा उर्दू के बोलने वाले हैं, वहां पर उसकी दूसरी जुबान बनाया जाएगा, स्कूलों में उसके पढ़ने का इंतजाम किया जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक साल हो गया, आपने उर्दू के लिए, कॉमन

मिनिमम प्रोग्राम के इस बुनियादी मसले को लागू करने के लिए , क्या कदम उठाए? आपके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ? उर्दू को इंसाफ दिलाने के लिए, दूसरी जुबा बनाने के लिए आपने क्या इनीसिएटिव लिए हैं ? राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उर्दू को बढ़ावा देने की बात कहीं थी , लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ । बजट में उर्दू का नाम लिया गया, लेकिन कोई आंवटन उसके लिए नहीं किया गया, उसके लिए कोई रकम मुकर्रर नहीं की गई । कहा गया कि टीचर्स लगाए जाएंगे । मेरे अजीज , आप उर्दू की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता ।

सब मेरे चाहने वाले हैं मगर कोई नहीं ।
मैं खुद इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं।

महोदय, उर्दू के साथ जो ज्यादती होती रही है, उसमें कुछ लोग यह कहते हैं कि चूंकि यह अकलियतों की जुबा हैं , मैं इस बात से इतफाक नहीं करता हूं । उर्दू अकलियतों की जुबा नहीं है, लेकिन कुछ लोग उर्दू के साथ जुल्म करते हैं, यह समझ कर कि अकलियतों की जुबा है और इसलिए शायद उर्दू खत्म हो गई , तो अकलियत भी जी हैं, वे कमजोर हो जाएंगी ।

जुल्म उर्दू पर भी होता है इस निस्बत से,
लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं।

महोदय, गलतफहमी जो हैं, वह दूर होनी चाहिए । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने जो यह एक बहुत बड़ा सर्वांशिक्षा अभियान का प्रोग्राम बनाया है, उसमें उर्दू को आप कहां जगह दे रहे हैं ? उर्दू को उसमें कितना हिस्सा मिलने वाला हैं ? क्योंकि उर्दू से जुड़े हुए लोग, उर्दू के पढ़ने वाले लोग जो हैं , उन पर पिछले 55-56 साल मे जुल्म हुआ हैं । इसलिए आज उनका सबसे ज्यादा हक बनता हैं, वे ज्यादा पिछड़े हुए हैं । अगर आपको पूरे देश को शिक्षित करना है, तालीम-याफ्तार बनाना हैं, तो उनके लिए आपको उर्दू पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा । जब तक आप इसके लिए रकम मुकर्रर नहीं करेंगे, तब तक जो राज्य की सरकारें हैं, वे उस पर अमल नहीं करेंगी ।

महोदय, यह जरूरी है कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाए । जब तक उर्दू को रोजगार से नहीं जोड़े गे तब तक बात नहीं बनेगी । उर्दू को रोजगार से आप कैसे जोड़ेंगे ? आप उर्दू का टी.वी चैनल शुरू कीजिए । सारी जुबानों के शुरू हो गए , उड़िया का हो गया, बंगला का हो गया , लेकिन उर्दू का चैनल शुरू करने मे आपको क्या तकलीफ हैं ? उर्दू की कमजोरी यह है कि उर्दू पूरे हिन्दुस्तान में बोली जाती हैं । यह हिन्दुस्तान की छठी सबसे बड़ी जुबान है । कश्मीर से तमिलनाडु तक उर्दू के स्कूल हैं, उर्दू के बोलने वाले हैं , उर्दू के चाहने वाले हैं, लेकिन अभी भी कश्मीर के अलावा कोई स्टेट इसमें आगे नहीं है। इसलिए उर्दू के लिए कोई मांग करने वाला नहीं है, उर्दू के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है । उर्दू का टी.वी . चैनल आप शुरू करेंगे , तो उससे रोजगार मिलेगा , उर्दू का रेडियों

स्टेशन शुरू करेंगे, तो उससे भी रोजगार मिलेगा। इस सबसे बढ़कर मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक उर्दू के टीचर्स नहीं होंगे, जब तक उर्दू पढ़ाने का इंतजाम नहीं होगा, रोजगार मिलेगा और न उर्दू होगी।

बिहार में जब 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, जगन्नाथ मिश्र जी ने, मैं उनको आज याद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इसे दूसरी जुबां का दर्जा दिया था और हमें अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि उर्दू को एक नई जिंदगी मिलने वाली है। जब 1986 में इसे दूसरी जुबां बनाया गया, तो हुआ क्या? कि बिहार में 1986 में जगन्नाथ मिश्र जी ने उर्दू को जब दूसरी जुबां बनाया, तो 600 ट्रांसलेटर्स लगाए गए 300ट्रांसलेटर्स और 300 असिस्टेंट ट्रांसलेटर्स, लेकिन आज वे ट्रांसलेटर्स उर्दू का काम नहीं कर रहे बल्कि फाइलिंग करने का काम करते हैं। उनसे उर्दू का काम नहीं लिया जाता और उसके बाद से तो बिहार में कोई उर्दू का ट्रांसलेटर अपोइंट ही नहीं किया गया जिसे आप कहते, बहाल नहीं किया गया। पिछले 30साल के अंदर आपने उर्दू का कोई ट्रांसलेटर बहार नहीं किया, उन 600 के बाद मैं और उनमेंभी जो रिटायर हुए, वे जाते गए। ये ट्रांसलेटर्स बी.ए ग्रेजुएट थे, लेकिन ग्रेजुएट के साथ क्या ज्यादती की, कि उनको आपने आपने तनख्याह दी, जो ग्रेड दिया, वह इंटर वाले को दिया जाता हैं, दूसरा अगर कोई किसी पोस्ट पर ग्रेजुएट आ रहा है तो उसको तनख्याह दूसरी मिलेगी और उर्दू का जो ग्रेजुएट होगा उसको तनख्याह दूसरी मिलेगी। आपने साफ कर दिया कि उर्दू को हम दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे की जुबां समझते हैं, उर्दू पढ़ने वालों हम को दूसरे दर्जे का समझते हैं। उर्दू में इन्सिहान देने वाले और काम करने वाले को बराबर का हक देने को हम तैयान नहीं हैं। हम उसके लिए भी तैयार थे, लेकिन वह भी आपने नहीं किया। जगन्नाथ मिश्र जी ने ऐलान किया था तमाम थानों के लिए चूंकि थानों का काम बिहार में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के अंदर नॉथ इंडिया में सारे थानों का काम, पुलिस स्टेशन का काम, कोर्ट का काम 1947 तक, बल्कि 1955 - 56 तक उर्दू में होते रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उर्दू के लोग लगाए नहीं गए तो पुराने सारे जो रिकार्ड पड़े हुए हैं, उन रिकार्ड में कोई जा नहीं सकता, इसलिए मिश्र जी ने कहा था कि हर थाने में कम से कम एक मुर्शी या एक आदमी उर्दू जानने वाला लगाया जाएगा मैं आपसे बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर कहीं किसी थाने में उर्दू जानने वाले को एपायंट नहीं किया गया। जब मैं बिहार की बात कर रहा हूं तो यह मानकर चलता हूं कि पूरे देश की बात कर रहा हूं, जहां जहां उर्दू हैं।

महोदय, इस वक्त चूंकि बिहार का सवाल है, इसलिए मैं बिहार पर ही जोर दूंगा। आप कुछ स्कूलों में जो टीचर्स लगाने वाले थे, वे उर्दू के टीचर्स आपने नहीं लगाए। आज भी हालत यह है कि 9000 जगह खाली हैं उर्दू के टीचर्स की यानी, 9000 लोगों को आप नौकरी दे सकते थे। उर्दू वाले उर्दू में बी.ए.एम.ए. करने के बाद भी भूखे मर रहे हैं। उन्हें अपना पेट काट कर उर्दू को जिन्दा रखना पड़ा रहा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई। बिहार के अन्दर 9000 टीचर्स की जगह खाली

हैं, वे टीचर्स नहीं लगाए गए। बिहार में 95 प्रतिशत जो गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं, उनमें उर्दू टीचर नहीं हैं। उर्दू जबान के जो बच्चे हैं, और जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उर्दू पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो टीचर रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह दूसरे उर्दू के टीचर नहीं लगाए जा रहे हैं, तो सूरत -ए-हाल यह है।

मदरसों के लिए आपने कहा था कि 2900 मदरसे मंजूरशुदा हैं, लेकिन उन मदरसों के उस्ताद भी 15 वर्ष से सड़को पर हैं, उनको तनख्याहें नहीं मिलती हैं, पिछले दो वर्ष से उन्हें नहीं मिली। आपने बीस साल पहले बिहार में मज़हर-उल-हक अरबी-फारसी-उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था, वह आज तक किताबों में ही हैं पिछले दिनों सुना कि किसी शर्फुदीन साहब को वाइस चान्सलर बना दिया गया, लेकिन अभी तक उनका कोई आफिस नहीं है, कोई कैम्पस नहीं है, यह सब आपने उर्दू के साथ किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम मदरसों की बात करते हैं, अगर सारे मदरसों की किसी उर्दू यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दिया जाए, तो उन मदरसों के बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलेंगे। वे जब उन मदरसों से पढ़ कर कालेज में आएंगे, तो ग्रेजुएशन कर सकेंगे, रोगजार ले सकेंगे और आगे जाकर यूजकुल शहरी बन सकेंगे। आजकल तो यह इल्जाम लगाना बहुत आसान होता है कि मदरसों से निकलने वाले आतंकवादी होता है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि मदरसों ने उर्दू को जिन्दा रखा है, जो काम हुकूमत का था, जो काम इस मुल्क के लोगों का था। आपने उर्दू को खत्म करके एक तहजीब को, एक पूरे दौर को, एक पूरी तारीख को मिटा दिया। जबाने जो होती हैं, वे मुश्किल से बनती हैं, उसमें हजारों साल लग जाते हैं, लोगों को खून -ए-जिगर पिलाना पड़ता।

आज दुनिया में कोई भी कौम अपनी ज़बान से जानी जाती हैं चाहे वह फ़ैंच हो, चाहे जर्मन हो और यहां तक कि लोगों ने जो अपने देश बनाए हैं, वे भी ज़बानों के नाम से बने हैं। लेकिन एक ज़बान को मिटा दिया जाता है, इतनी जबरदस्त ज़बान, जिसमें इस उर्दू के अन्दर पूरी गंगा-जमुनी तहजीब, पूरे 2000 साल का हिन्दुस्तान निचुड़ कर आया था। उर्दू की बातें तो बहुत की जाती हैं, उसकी तारीफ भी की जाती है, लेकिन उर्दू को आहिस्ता-आहिस्ता, स्लों प्वाइजन देकर इस मुल्क में खत्म किया गया, फिर चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो। उर्दू को जो हक मिलना चाहिए था, मुझे आज कहने दीजिए, वह नहीं मिला और वह हक इसलिए भी नहीं मिला कि उर्दू वाले भी पूरी ताकत से अपनी बात नहीं कहते हैं।

मान्यवर, यदि आप उर्दू को रोजगार से नहीं जोड़ेगे, सर्व शिक्षा आभियान में यदि उर्दू को उसका हिस्सा नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आज हम उत्तर प्रदेश में उर्दू यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, वह क्यों बनाना चाह रहे हैं? वह इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी होगी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके साथ, उस उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत हम बहुत से आई.टी. आई. भी शुरू कर सकेंगे, जो मदरसों में काम करेंगे। बहुत सारे मदरसे उससे एफिलिएट

हो सकेंगे। उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों जब मदरसे को पास कर लेते हैं तब वे कहां जाए? उन्हें किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, बी.ए.एड. में दाखिला नहीं मिलता। बी.एड. का कॉलेज हम इसी यूनिवर्सिटी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें मदद करने के बजाए आप उसमें रुकावट डाल रहे हैं। श्री जय राम रमेश जी, उसमें आप रुकावट डाल रहे हैं, वह रुकावट आप मत डालिए।...(व्यवधान).....

श्री जय राम रमेश (आन्ध्र प्रदेश) : महोदय, यह बिल्कुल गलत हैं, वे बुनियाद हैं।

श्री शाहिद सिद्धिकी : मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं।

श्री जय राम रमेश : कानून के खिलाफ चान्सलर का एपाइटर्मेंट हो रहा है, इसलिए इस यूनिवर्सिटी के काम में रुकावट आ रही है।

श्री उपसभापति : इन्होंने बहुत बढ़िया उर्दू में बात की है।....(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्धिकी : मान्यवर, अब तो वह भी विड्रा हो गया है। अब तो कम से कम, खुदा के लिए इस यूनिवर्सिटी का बनने दीजिए। मैं श्री देवगौड़ा जी को याद करना चाहता हूं, जब वे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई थी, लेकिन उससे पहले या उसके बाद उर्दू के लिए कोई काम नहीं हुआ। आज आपके पास भी कई राज्यों में सरकारें हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर एक –दो उर्दू यूनिवर्सिटीज शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि उर्दू वालों को रोजगार भी मिलेगा और उन्हें आगे जाने का मौका भी मिलेगा। जहां तक उर्दू के टीचर्स की बात है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो उर्दू में ग्रेजुएशन करते हैं, जो उर्दू में बी.ए.या एम.ए करते हैं। काम्पिटीशन इतना ज्यादा है कि उर्दू टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों में दाखिला नहीं मिलता। जब हमें टीचर्स की जरूरत होती है, तो हमारे पास उर्दू का बी.एड. किया हुआ टीचर नहीं होता, इसलिए आप खास तौर पर उर्दू के टीचर आगे नहीं आ पाएंगे इसी तरह से यह सारा सिसिला जुड़ेगा और उर्दू मेन –स्ट्रीम में आएगी, जिससे इस मुल्क का भला होगा, इस मुल्क का फायदा होगा और इस मुल्क की शान बढ़ेगी।

हम पाकिस्तान से कहते हैं कि उर्दू तुम्हारी जबान नहीं हैं, यह हिन्दुस्तान की जबान है और यह हम कब से कहते हैं, सर उठा कर कहते हैं और सच्चाई भी यही हैं कि हिन्दुस्तान को जबान है। पाकिस्तान जितना भी उसे अपनाना चाहें, दस सदिया तक भी वह उसे अपनी जबान नहीं बना सकता क्योंकि उर्दू, हिन्दुस्तान की जबान हैं और हिन्दुस्तान की जबान ही रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उर्दू को कोई खत्म नहीं कर सकता, उर्दू खत्म नहीं हुई है। आज महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आन्ध्र प्रदेश में, जहां-जहां भी उर्दू का कॉम्प्युटीशन मकामी जबान से नहीं था और जहां उर्दू को

जबरदस्ती दबाया नहीं गया, वहां उर्दू के अंदर इतना डायनीमिज्म था कि उर्दू अपनी ताकत से अपने आप आगे बढ़ी। उर्दू वालों ने उर्दू अखबार वालों ने, उर्दू टीचर्स ने अपना पेट काट-काट कर उर्दू को पाला है।

महोदय में सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उर्दू के अखबारों के साथ इतनी ज्यादती होती हैं क्योंकि हमारी कोई सरकारी नहीं हैं। गुजराती के अखबार को गुजरात की सरकार से इश्तिहार मिलते हैं, बंगाली अखबार को बंगाल की हुक्मत की पुश्त पनाही मिलती हैं, लेकिन उर्दू अखबारों को किसी की पुश्त पनाही और बैंकिंग नहीं मिलती हैं, उन्हें कोई इश्तिहार नहीं मिलते हैं। उर्दू के अखबार वाले अपना पेट काट-काट कर इन उर्दू अखबारों को चलाते हैं, उसके लिए उन्हें आपको जोड़ना होगा। आप यह बिहार में कीजिए और मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में कीजिए। मैं जानता हूं कि यहां पर मुझसे बेहतर बोलने वाले लोग हैं।.. (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : अभी 11 लोग बोलने वाले हैं, जरा समय का भी ख्याल रखिए।

श्री शहिद सिद्दिकी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ... (व्यवधान) .. मैं दाग के मशहूर शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं :-

“उर्दू है इसका नाम सभी जानते हैं “दाग”
सारे जहां में धूम , हमारी जुबां की हैं,
लबो रुखसार गेसू बोलता हैं,
सरों पे चढ़ के जादू बोलता हैं
अभी तहजीब जिन्दा हैं हमारी ,
अभी ये शख्स उर्दू बोलता हैं

شری شاپد صدیقی "اترپرڈیش": دُبّی چیئرمین صاحب، میں آپ کا ہمت شکرگزار بون کر آج آپ نے ہمیں اردو پر بات کرنے کا موقع دیا، کیونکہ کسی باوس میں ایسے موقع ہست کم آتے ہیں کہ اردو پر بات ہو۔ 55 سالوں سے اردو کا جو درد ہے، میں اسے ہمیں بیان نہیں کروں گا، اردو کے

† Transliteration in Urdu Script.

ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہیں، نالنصافیاں ہوتی رہیں، میں وہ بیان نہیں کروں گا، کیوں کہ وہ بہت لمبی داستان ہے، اس کے لئے بہت وقت چاہئے۔ میں آج جو بات کروں گا، اس میں ہمار میں اردو کی بھی بات کروں گا لیکن ہمار میں جو اردو ہے وہ آئیسویلیشن میں نہیں ہے۔ آپ صرف ہمار میں اردو کو زندہ نہیں رکھ سکتے، آگرہ پورے پندوستان میں اردو کا قتل ہو گا۔ آگرہ ہمار میں اردو کو زندہ رکھنا ہے تو روزگار سے اسے جوڑنا ہو گا، پورے پندوستان میں اردو کو اس کا حق دینا ہو گا۔ مہودے، اس لئے میں پورے پندوستان کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری بات کروں گا۔ جو پچھلی بتیں ہیں۔ میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ میں آج کی بات کرتا ہوں کہ جو کامن منیم پروگرام بننا، اس میں وعدہ کیا گیا کہ اردو کو اس کا حق دیا جائے گا، جہاں پر 10 فیصدی سوزیادہ اردو کے بولنے والے ہیں، وہاں پر اس کو دوسری زبان بنایا جائے گا، اسکلئون میں اس کے پڑھنے کا انتظام کیا جائے گا۔ میں منتری جی سے جانتا چاہوں گا کہ ایک سال پوچھا گیا، آپ نے اردو کے لئے، کامن منیم پروگرام کے اس بنیادی مسئلے کو لاگو کرنے کے لئے، کیا قدم اٹھائے؟ آپ کے منترالیہ نے کیا قدم اٹھائے ہیں؟ اردو کو انصاف دلانے کے لئے، دوسری زبان بنانے کے لئے آپ نے کیا انی شیشیوں لئے پیش راشٹرپتی جی نے اپنے بھاشن میں اردو کو بڑھاوا دینے کی بات کہی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ بجٹ میں اردو کا نام لیا گیا، لیکن کوئی آونٹن اس کے لئے نہیں کیا گیا، اس کے لئے کوئی رقم مقرر نہیں کی گئی۔ کہا گیا کہ نیچرس لگائے جائیں گے۔ میرے عزیز آپ اردو کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لئے کوئی کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

سب میرے چاہئے والے ہیں، مگر کوئی نہیں
میں خود اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں
مہودے، اردو کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی ہے، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اقلیتوں کی زبان ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اردو اقلیتوں کی زبان نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اردو

کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ سمجھہ کر کے اقلیتوں کی زبان ہے اور اس لئے شاید اردو ختم ہو گئی، تو اقلیتیں
بھی جو ہیں، وہ کمزور ہو جائیں گی۔

ظلم اردو پر بھی ہوتا ہے اس نسبت سے
لوگ اردو کو مسلمان سمجھہ لیتے ہیں

مہودے، غلط فہمی جو ہے، وہ دور بونی چاہئے۔ میں آپ سے یہ جانتا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ ایک
بہت بڑا سرو شکشا ابھیان کا پروگرام بنایا ہے، اس میں اردو کو آپ کہاں جگہ دے رہے ہیں؟ اردو کو اس
میں کتنا حصہ ملنے والا ہے؟ کیونکہ اردو سے جڑے بوئے لوگ، اردو کے پڑھنے والے لوگ جو ہیں، ان
پر پچھلے 55-56 سال میں ظلم ہوا ہے۔ اس لئے آج ان کا سب سے زیادہ حق بتتا ہے، وہ زیادہ پچھڑے
ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو پورے دیش کی شکست کرنا ہے، تعلیم یافت بنانا ہے، تو ان کے لئے آپ کو اردو پر
زیادہ خرچ کرنا پڑیگا۔ جب تک آپ اس کے لئے رقم مقرر نہیں کریں گے، تب تک جو راجیہ کی سرکاریں
ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کریں گی۔

مہودے، یہ ضروری ہے کہ اردو کو روزگار سے جوڑا جائے۔ جب تک اردو کو روزگار سے نہیں جوڑیں
گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اردو کو روزگار سے آپ کیسے جوڑیں گے؟ آپ اردو کا ٹوی چینل شروع
کیجئے۔ ساری زبانوں کے شروع ہو گئے، اڑیہ کا ہو گیا، بنگلہ کا ہو گیا، لیکن اردو کا چینل شروع کرنے میں
آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اردو کی کمزوری یہ ہے کہ اردو پورے ہندوستان میں بولی جاتی ہے۔ یہ ہندوستان
کی چھٹی سب سے بڑی زبان ہے۔ کشمیر سے تمل ناؤ تک اردو کے اسکول پیں، اردو کے بولنے والے
ہیں، اردو کے چاہنے والے ہیں، لیکن ابھی بھی کشمیر کے علاوہ کوئی استثیت اس میں آگئی نہیں ہے اس
لئے اردو کے لئے کوئی مانگ کرنے والا نہیں ہے، اردو کے لئے کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ اردو کا ٹوی
چینل آپ شروع کریں گے، تو اس سے روزگار ملے گا، اردو کا ریڈیو اسٹیشن شروع کریں گے تو اس

سے روزگار ملے گا، اردو کا ریڈیو اسٹیشن شروع کریں گے، تو اس سے بھی روزگار ملے گا۔ اس سب سے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہونگا کہ جب تک اردو کے ٹیچرس نہیں ہوئے، جب تک اردو کا انتظام نہیں پوگا، نہ روزگار ملیگا اور نہ اردو پوگی۔

ہمارا میں جب 1986ء میں کانگریس کی سرکار تھی، جگن ناتھ مشرجی نے، میں ان کو آج یاد کرتا ہوں اور ان کو بدھائی دیتا ہوں، کہ انہوں نے اسے دوسری زبان کا درج دیا تھا اور ہمیں انہیں سے میں ایک امید کی کرنے نظر آئی تھی کہ اردو کو ایک نئی زندگی ملنے والی ہے۔ جب 1986ء میں اسے دوسری زبان بنایا گیا، تو کیا ہوا؟ ہمارا میں جگن ناتھ مشرجی نے اردو کو جب دوسری زبان بنایا تو 600 ٹرانسلیٹر لگائے گئے، 300 ٹرانسلیٹر اور 1300 اسیٹنٹ ٹرانسلیٹر، لیکن آج وہ ٹرانسلیٹر اردو کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ فائلنگ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان سے اردو کا کام نہیں لیا جاتا اور اس کے بعد سے تو ہمارا میں کوئی اردو کا ٹرانسلیٹر اپنائی ہی نہیں کیا گیا، جسے آپ کہتے ہیں بحال نہیں کیا گیا۔ پہلے 30 سال کے اندر آپ نے اردو کا کوئی ٹرانسلیٹر بحال نہیں کیا، ان 600 کے بعد میں اور ان میں بھی جو ریٹائر پوئے، وہ جاتے گئے۔ یہ ٹرانسلیٹر اے گرجویٹ تھے، لیکن گرجویٹ کے ساتھ کیا زیادتی کی، کہ ان کو آپ نے جو تنخواہ دی، جو گریڈ دیا، وہ انٹر والے کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا اگر کوئی کسی پوسٹ پر گرجویٹ آ رہا ہے تو اس کی تنخواہ دوسری ملیگی اور اردو کا جو گرجویٹ ہو گا اس کو تنخواہ دوسری ملیگی۔ آپ سے صاف کر دیا کہ اردو کو ہم دوسرے، تیسرا، چوتھے، درجے کی زبان سمجھتے ہیں، اردو پڑھانے والوں کو ہم دوسرے درجے کا سمجھتے ہیں۔ اردو میں امتحان دینے والے اور کام کرنے والے کو پر ابر کا حق دینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کے لئے بھی تیار ہے، لیکن وہ جبھی آپ نے نہیں کیا۔ جگن ناتھ مشرجی نے اعلان کیا تھا تمام تھانوں کے لئے، چونکہ تھانوں کا کام ہمارا میں ہی نہیں، پورے ہندوستان کے اندر، نارتھ انڈیا میں

سارے

تھانوں کا کام، پولیس اسٹیشن کا کام، کورٹ کا کام 1947 تک، بلکہ 1955-56 تک اردو میں ہوتا رہا۔ لیکن آئسٹے آئسٹے جب اردو کے لوگ لگائے نہیں گئے، تو پرانے سارے جو ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، ان ریکارڈ میں کوئی جانہیں سکتا، اس لئے مشراجی نے کہا تھا کہ پر تھانے میں کم سے کم ایک منشی یا ایک آدمی اردو جانے والا لگایا جائے گا۔ میں آپ سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کے اندر کہیں کسی تھانے میں اردو جانے والے کو اپنا نہیں کیا گیا۔ جب میں ہماری بات کر رہا ہوں، تو یہ مان کر چلتا ہوں کہ پورے دیش کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں اردو ہے۔

مبودے، اس وقت چونکہ ہمارا سوال ہے۔ اس لئے میں ہمار پر بڑی زور دوں گا۔ آپ کچھ اسکولوں میں جو ٹیچرس لگانے والے تھے۔ وہ اردو کے ٹیچرس آپ نے نہیں لگائے۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ 9000 جگہ خالی ہیں اردو کے ٹیچرس کی، یعنی 9000 لوگوں کو آپ نوکری دے سکتے ہیں۔ اردو والے اردو میں بے اسے، ایم اے کرنے کے بعد ہموکوں مر رہے ہیں۔ انہیں اپنا پیٹ کاٹ کر اردو کو زندہ رکھنا پڑتا ہے، لیکن انہیں نوکری نہیں دی گئی۔ ہمارے اندر 9000 ٹیچرس کی جگہ خالی ہے، وہ ٹیچرس نہیں لگائے گئے۔ ہر میں 95 فیصد جو گورنمنٹ پائی اسکولس پیں، ان میں اردو ٹیچرس نہیں ہیں۔ اردو زبان کے جو بچے ہیں اور اردو پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں اردو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو ٹیچرس رینائیروں پر ہیں، ان کی جگہ دوسرے اردو کے ٹیچر نہیں لگائے جا رہے ہیں، تو صورت حال یہ ہے۔ مدرسون کے لئے آپ نے کہا تھا کہ 2900 مدرس سے منظور شدہ ہیں لیکن ان مدرسون کے استاد بھی 15 سالوں سے سڑکوں پر ہیں، ان کی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، پچھلے دو سال سے انہیں تنخواہیں نہیں ملیں۔ آپ نے یہ سال پہلے ہمارے میں مظہر الحق عربی-فارس-اردو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، وہ آج تک کتابوں میں ہی ہے، پچھلے دونوں سناک کسی شرف الدین صاحب کو وائس چانسلر بنا دیا گیا، لیکن ابھی تک ان کا کوئی آفس نہیں ہے، کوئی کیمپس نہیں ہے، یہ سب آپ نے اردو کے ساتھ کیا، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مدرسون کی بات کرتے ہیں، اگر سارے مدرسون کو کسی اردو یونیورسٹی سے ایفی لی ایسٹ کر دیا جائے، تو ان

مدرسون کے بچے گریجویٹ ہو کر نکلیں گے، وہ جب ان مدرسون سرپڑھ کر کالج میں آئیں گے، تو گریجوشن کر سکیں گے، روزگار لے سکیں گے اور آگے جا کر یوزفل شہری بن سکیں گے۔ آج کل قیہ الزام لکانا ہت آسان ہوتا ہے کہ مدرسون سے نکلنے والے آنکوادی ہوتے ہیں، لیکن میں پہنچا پتا ہوں کہ مدرسون نے اردو کو زندہ رکھا ہے، جو کام حکومت کا تھا، جو کام اس ملک کے لوگوں کا تھا۔ آپ نے اردو کو ختم کر کے ایک تمذیب کو، ایک پورے دور کو، ایک پوری تاریخ کو مٹا دیا۔ زبانیں جو بوقتی ہیں، وہ ہست مشکل سے بنتی ہیں، اس میں بزاروں سال لگ جاتے ہیں، لوگوں کو خون جگر پلانا پڑتا ہے۔ آج دنیا میں کوئی بھی قوم اپنی زبان سے جانی جاتی ہے چاہے وہ فرینچ ہو، چاہے وہ جرمن ہو اور یہاں تک کہ لوگوں نے جو اپنے دیش بنائے ہیں، وہ بھی زبانوں کے نام سے بنے ہیں۔ لیکن ایک زبان کو مٹا دیا جاتا ہے، اتنی زبردست زبان، جس میں اس اردو کے اندر پوری گنگا جمنی تمذیب، پورے 2000 سال کا ہندوستان چھوڑ کر آیا تھا۔ اردو کی باتیں تو ہست کی جاتی ہیں، اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن اردو کو آپستہ آپستہ سلوپوانzen دیکر اس ملک میں ختم کیا گیا پھر چاہے وہ ہمارا بو، اترپردیش ہو، دبلي ہو۔ اردو کو جو حق ملنا چاہئے تھا، مجھے آج کہنے دیجئے، وہ نہیں ملا اور وہ حق اس لئے بھی نہیں ملا کہ اردو والے بھی پوری طاقت سے اپنی بات نہیں کہتے ہیں۔

مانیور آگر آپ اردو کو روزگار سے نہیں جوڑیں گے، سرشکشا ابھیان میں اگر اردو کو اس کا حصہ نہیں دیں گے تو تک بات نہیں بننے گی۔ آج ہم اترپردیش میں اردو یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں، وہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لئے بنانا چاہ رہے ہیں کہ اردو یونیورسٹی ہوگی، وہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لئے بنانا چاہ رہے ہیں کہ اردو یونیورسٹی ہوگی، مولانا محمد علی جوہر اردو یونیورسٹی، اس کے ساتھ، اس اردو یونیورسٹی کے تحت ہم ہست سے آئیں آئی بھی شروع کر سکیں گے، جو مدرسون میں کام کریں گے، ہست سارے مدرسے اس سے ایفی لی ایٹ ہو سکیں گے، ان مدرسون میں پڑھنے والے بچے جب مدرسے سے پاس کر لیتے ہیں تب وہ کہاں جائیں؟ نہیں کسی کالج میں داخل نہیں ملتا، بی ایڈ

میں داخل نہیں ملتا۔ بے ایڈ کالج ہم اسی یونیورسٹی سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مددگرنے کے بجائے آپ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ شری چے رام رمیش جی، اس میں آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ رکاوٹ آپ مت ڈالئے..... مداخلت.....

شری چے رام رمیش: مہودے، یہ بالکل غلط ہے، یہ بنیاد ہے۔

شری شاہد صدیقی: میں معاف چاہتا ہوں، معاف چاہتا ہوں۔

شری چے رام رمیش: قانون کے خلاف چانسلر کا اپائٹمنٹ ہو رہا ہے، اسی لئے اس یونیورسٹی کے کام میں رکاوٹ آری ہے۔

شری اپ سہاپی: انہوں نے بہت بڑھیا اردو میں بات کی ہے..... مداخلت.....

شری شاہد صدیقی: مانیور، اب تو وہ بھی ودھرا ہو گیا ہے۔ اب تو کم سے کم، خدا کے لئے اس

یونیورسٹی کو بننے دیجئے۔ میں شری دیو گوڑا جی کو یاد کرنا چاہتا ہوں، جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے،

انہوں نے ایک اردو یونیورسٹی بنائی تھی، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد اردو کے لئے کام نہیں پوا۔

آج آپ کے پاس ہی کئی راجیوں میں سرکاریں ہیں۔ میں مانئے منتري جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر

ایک دو اردو یونیورسٹیز شروع کیجئے۔ اس سے کیا پوگاک اردو والوں کو روزگار بھی ملے گا اور انہیں

آگے جانے کا موقع بھی ملے گا۔ جہاں تک اردو کے ٹیچرس کی بات ہے، سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ

جو اردو میں گریجویشن کرتے ہیں، جو اردو میں بے اے یا ایم اے کرتے ہیں، کمپیویشن اتنا زیادہ ہے کہ

انہیں ٹیچرس ٹریننگ کالج میں داخلہ نہیں ملتا۔ جب ہمیں ٹیچرس کی ضرورت پوتی ہے، تو پمارے

پاس اردو کا بے ایڈ کیا ہوا ٹیچر نہیں ہوتا، اس لئے آپ خاص طور پر اردو کے ٹیچرس ٹریننگ کالج

بنائیے۔ اگر آپ اردو کے ٹیچرس ٹریننگ کالج نہیں بنائیں گے تو اردو کے ٹیچرس آگے نہیں آپاں گے،

اسی طرح سے یہ سارا سلسلہ جڑے گا اور اردو میں اسٹریم میں آئے گی، جس سے اس ملک کا بہلا

پوگا، اس ملکا کا فائدہ ہوگا اور اس ملک کی شان بڑھے گی۔

ہم پاکستان سے کہتے ہیں کہ اردو تمہاری زبان نہیں ہے، یہ بندوستان کی زبان ہے اور یہ ہم فخر سے

کہتے ہیں، سراہب اکر کہتے ہیں اور سچائی بھی یہی ہے کہ یہ بندوستان کی زبان ہے۔ پاکستان جتنا بھی

ا سے اپنانا چاہے، دس صدیوں تک بھی وہا سے اپنی زبان نہیں بنا سکتا کیونکہ اردو، بندوستان کی زبان

ہے اور

ہندستان کی زبان بھی رہے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اردو ختم نہیں بوئی ہے۔ آج مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، آندرہ پردیش میں، جہاں جہاں بھی اردو کا کمپیشن مقامی زبان سے نہیں تھا اور جہاں اردو کو زبردستی دبایا نہیں گیا، وہاں اردو کے اندر اتنا ڈائنا مز تھا کہ اردو اپنی طاقت سے اپنے آپ آگے بڑھی، اردو والوں نے، اردو اخبار والوں نے، اردو ٹیچر نے اپنا پیٹ کاٹ کر اردو کو پلا ہے۔

مہودے، میں سرکار سے یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے اخباروں کے ساتھ اتنی زیادتی بوئی ہے کیونکہ بماری کوئی سرکار نہیں ہے۔ گجرات کے اخبار کو گجرات کی سرکار سے اشتہار ملتے ہیں، بنگالی اخبار کو بنگال کی حکومت کی پشت پناہی ملتی ہے، لیکن اردو اخبار کو کسی کی جھی پشت پناہی اور بیکنگ نہیں ملتی ہے، انہیں کوئی اشتہار نہیں ملتے ہیں۔ اردو کے اخبار والے اپنا پیٹ کاٹ کر ان اخباروں کو چلاتے ہیں، اس کے لئے انہیں آپ کو جوڑنا ہوگا۔ آپ یہ ہمارے میں کیجھے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندستان میں کیجھے۔ میں جانتا ہوں کہ جہاں پر مجھ سے ہتر بولنے والے لوگ ہیں۔..... مداخلت.....

شروع اپ سہاپتی: ابھی گیارہ لوگ بولنے والے ہیں، ذرا وقت کا خیال رکھئے۔

شروع شاہد صدیقی: مہودے، میں اپنی بات سمایپت کرتا ہوں مداخلت..... میں داغ کے مشہور شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔
 اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ
 سارے جہاں میں دھوم بماری زبان کی ہے
 اور لب و رخسار گیسو بولتا ہے
 سروں پر چرہ کر جادو بولتا ہے
 ابھی تمذیب زندہ ہے بماری
 ابھی یہ شخص اردو بولتا ہے

एक माननीय सदस्य : क्या आप उर्दू में कुछ बोलेंगे... ... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : जी हाँ , बोलूंगा। ... (व्यवधान).... The Chair has an inhearned right to put question.

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा) : माननीय उपसभापति जी , बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात की खुशी भी हैं और गम भी हैं , खुशी इस बात की हैं कि बड़ी मुश्किल से उर्दू के लिए बोलने का मौका मिला ओर दुःख यह है कि वह जुबान, जिसने हिन्दुस्तान की आजादी को लाने में सबसे ज्यादा काम किया, आज उसकी हिफाजत के लिए हम लोग इस हाउस में खड़े हो कर कहें कि इसको मदद करो। यह वही जबान हैं, जिसमें इकलाब लफ्ज दिया था और वह “ इकलाब जिदाबाद ” का लफ्ज देने वाले अकेले उर्दू वाले ही नहीं थे, साउथ में भी वहीं लफ्ज था। यह वही जबान है जो आज भी कहती हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा और बाद में वही कौमी तराना बना। यह वर्हीं जबान हैं जिसमें हम जब किसी जगह जाते हैं तो “ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में मैं हैं, देखना है जोर कितना बाजु –ए-कातिल मैं हैं ” गाया जाता है और हिन्दुस्तान में जब किसी जगह जरूरत पड़ती हैं कि लोगों में जोश दिलाया जाए या कहीं यह कहना पड़ता है कि देश भक्ति कहाँ हैं, तो फिर उर्दू को इस्तेमाल किया हैं। लेकिन जब उर्दू के लिए कुछ करना हो तो कुछ नहीं है उर्दू के दो दुश्मन हैं, मैं काफी समय से उर्दू के लिए काम कर रहा हूं, एक तो वे जिन्होंने इसे एक फिरके को जबान बना दिया और वह एक परचम लेकर खड़ा हो गया कि यह हमारी जबान हैं, हमें दो और दूसरे पोलिटिकल पार्टी वाले जो वोट बैंक बनाने के लिए इस जबान का इस्तेमाल करने लगे जबकि वहां इसका कुछ काम नहीं था। इसलिए मैं एक तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि उर्दू एक फिरके को जबान नहीं हैं। मुझे याद हैं कि जब ज्ञानी जेल सिंह जी होम मिनिस्टर बने , तो उन्होंने उर्दू में ओथ लिया , तो लोग कहने लगे कि यह क्या हो रहा है ? उन्होंने कहा कि मेरी तो जबान ही उर्दू है। जब चौधरी देवी लाल उप प्रधान मंत्री थे , तो जो भी उनके साथ काम करते थे, उन्हें देखते थे, वे उर्दू में ही नोट्स मांगते थे और उर्दू में की काम करते थे। ... (व्यवधान) ... जी हाँ मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हम भूल जाते हैं फिराक गोरखपुरी को, भूल जाते हैं आनन्द नारायण मुल्ला को, जगन्नाथ आजाद को या आज के लोगों की बात करे तो डा.गोपाचंद नारायण को, जाकिर को, जमनादास अख्तर को। आज भी जो उर्दू को रोजाना सबसे बड़ा अखबार है वह मुसलमान नहीं निकालते, वह जालन्धर से छपता है और उसका नाम हैं “ हिन्द समाचार ” largest circulated Urdu newspaper is stiti Punjab और वहा मुसलमान नहीं रहते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उर्दू जबान को कभी भी एक फिरके का जबान न समझा जाए और जब तक हम इस गलतफहमी से नहीं निकलेंगं, हम इस जबान की तरक्की नहीं कर पाएंगे।

दूसरी बात में यह बताना चाहता हूं कि जितना यह नॉर्थ इंडिया हैं, शुमाली हिन्दुस्तान, इसका सारा रिकार्ड उर्दू जबान में हैं। जितने भी पटवारियों के पास जो कुछ है भी हैं, वह उर्दू में हैं या आज भी यदि कहीं कोर्ट या कचहरी में जरूरत पड़ती है तो वह उर्दू में आता हैं। यदि उर्दू की पढ़ाई खत्म हो गई तो ये उर्दू के सारे रिकार्ड हैं, ये कौन पढ़ेगा ?

आजकल हमारे दो पंजाबों की दोस्ती चल रही हैं वे हिन्दुस्तान और पकिस्तान। इस दोस्ती को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उर्दू की जबान को कायम रखना होगा, वरना हम आपस में क्या दोस्ती करेंगे और मैं तो इससे भी आगे जाना चाहता हूं, मैंने नोट भेजा हैं, अगर हमारे देश से परशियन खत्म हो गई तो हमारी तारीख से क्या वापस आएगा और उसे कौन पढ़ेगा ? मैं तो सिखों को कहता हूं , हमारे गुरु ग्रंथ सहित में परसियन है, महाराजा रणजीत सिंह, जो हमारे सिख बादशाह थे, उनकी कोर्ट लैंग्वेज परसियन थी, पटियाला रियासत में सबकी परसियन कोर्ट लैंग्वेज थी, जितने archives हैं , सभी परसियन में हैं। मैं रिकमंड करना चाहता हूं कि ऐटलीस्ट जो पंजाबमें यूनिवर्सिटीज हैं , उनमें परसियन एक कम्प्लसरी लैंग्वेज रखियें। वहां पर उनको इनसेटिव दें, ताकि लोग परसियन पढ़ते रहें, वरना हमारे यह स्कालर जो उनसे संबंधित हैं वे अपना रिकार्ड देखने में असमर्थ होंगे।

सर, अभी मेरे दोस्त ने जो उर्दू के लिए कहा, सच्चाई तो यह हैं कि जिस दिन यहां पर यह सवाल आया था, उस दिन टैक्स्ट बुक्स की बात चली थी और मंत्री जी ने कहा था कि सब ऐवेलेबल हैं। दो दिन के बाद अंग्रेजी हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में उर्दू एकाडेमी जो दिल्ली की हैं, जिसके जिम्मे यह किताबें बांटना हैं, उनका एक बयान छपा कि हमारे पास किताबें नहीं हैं, हमारे पास नहीं आइयें। जिन्होंने किताबें देनी हैं, वे कह रहे हैं कि किताबें नहीं हैं, लोग हमें तंग कर रहे हैं और हालत यह हैं कि जो किताबें दसरीं और बारहवीं की साइंस, सोशल साइंस, मैथेमेटिक्स, ज्योग्राफी की बिल्कुल किताबें मार्केट में नहीं हैं, और छोटी जमातों की भी टैक्स्ट बुक्स नहीं हैं, उर्दू की टैक्स्ट बुक्स की ऐवेलेबिलिटी भारत में क्या दिल्ली में भी नहीं हैं। यहां पर मंत्री जी बैठे हैं, आप इसका कोई उपाय करिये। दिल्ली में यह हालत हैं कि यहां उर्दू बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा हैं, परसेटवाइज दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा अब भी उर्दू जुबान है और यहां सरकार के 1400 स्कूल हैं, लेकिन उर्दू के लिए सिर्फ 20 स्कूल हैं। यह हमारा कम्प्यूरिजन हैं। जमुना पार जहां दिल्ली की सतर परसेट आबादी रहती हैं, वहां पर सिर्फ एक स्कूल हैं जो उर्दू मीडियम हैं, उसमें सात हजार स्टूडेंट हैं और दूसरा स्कूल दिल्ली वाले जमुना पार नहीं खोल सके। जितने टीचर्स की डिमांड दिल्ली में हैं, इतने टीचर्स की वकेंसीज हैं, जिनको सरकार ने भरा नहीं हैं। अभी चार दिन पहले बिहार के स्कूलों के बारे में आया था कि वहां तीन हजार नब्बे वेकेंसीज खाली पड़ी हैं, जिसमें उर्दू टीचर्स चाहिएं और सरकार ने ये वकेंसीज भरी नहीं हैं। कभी किसी कचहरी का मसला ले लेते हैं और कभी कोई मसला ले लेते हैं। उर्दू टीचर्स की ऐवेलेबिलिटी बहुत कम हैं, टैक्स्ट बुक्स बहुत कम हैं, इसके अलावा मेरा यह कहना है कि उर्दू में वोकेशनल कोर्स नहीं हैं।

सरकार उर्दू टाइप राइटिंग के उर्दू स्टेनोग्राफी के प्रूफ रीडिंग के, प्रिंटिंग टैक्नालॉजी के इंतजाम करे जैसे हिन्दी के लिए अवार्ड देते हैं, उर्दू अवार्ड भी उसके बराबर का होना चाहिए और हर साल उर्दू के लिए अवार्ड दिया जाये। अभी आपने एक नेशनल कार्डिसिल आफ प्रोमोशन आफ उर्दू लैग्वेज बना रखी हैं, लेकिन वह काम क्या करती है? अभी –अभी कुछ दिन पहले मैंने उस कार्डिसिल के बारे में पढ़ा था। अभी एक कमेटी बनाई कमेटी की रिपोर्ट आई और उस कमेटी में वे लोग थे, जिन्हें उर्दू जुबान नहीं आती हैं। उसका बजट दस करोड़ रुपये हैं। उसमें से एक करोड़ 66 लाख रुपये स्टाफ पर खर्च होते हैं। अभी उन्होंने शुरू किया है कि उसी बजट से वे कम्युटर भी बाटेंगे, उसी बजट से वे अरबी की क्लासेज भी करेंगे। अगर सरकार ने यह करना हैं तो उसके लिए अलाहिदा बजट दिया जाए इसके अलावा जितने गवर्नमेंट आफ इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपन स्कूल हैं, उनमें उर्दू का कोई काम नहीं है, अगर कहीं हैं तो वहां स्टाफ नहीं हैं इसके लिए मेरी आप दख्खास्त है कि यह किया जाए। इस वक्त हिन्दुस्तान में जितनी रियासतें हैं, उनमें से सिर्फ 15 रियासतें ने उर्दू एकादमी बनाई हैं। बाकी जगह उर्दू एकादमी नहीं है और जहां पर हैं भी तो वहां पर इतना कम सरमाया उनके पास हैं, कि वह काम कर ही नहीं पाती हैं। इसके अलावा मैं जो अंतिम बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि मसला तो उर्दू का हैं लेकिन यहां सारी अविलयतें जुबाने खत्म हो रही हैं। उर्दू के लिए तो फिर भी पॉलिटिकल प्रैशर हैं, आपको वोट बैंक का भी फ्रिक हैं। पंजाबी जुबान के लिए पंजाब से बाहर भारत सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं करती। पंजाबी सैंकेड लैग्वेज है दिल्ली में, एक रुपए का भी बजट नहीं है। हिमाचल और हरियाणा पंजाब से निकले हैं, पंजाबी कम्पलसरी थी अब उनमें पंजाबी जुबान बिल्कुल नहीं है। अभी 6महीने हरियाणा में पंजाबी को सैंकेड लैग्वेज किया गया। हिमाचल सरकार ने तो यह किया है, माझनोरिटीज कमीशन ने यह रिकमेड किया कि आप तो पंजाब से आए हो, पंजाबी लैग्वेज को ऑप्सनल कर दो, यह उनकी केबिनेट में गया, फिर असेम्बली में पास किया, हम पंजाबी नहीं कर सकते। पंजाबी जुबान का यह हाल है। एक बौद्ध कौम है, वह भी माझनारिटी कम्युनिटी है। उनकी बौद्धि जुबान है, आज तक सरकार ने उनकी बौद्धि जुबान को रिमंडेशन नहीं दी है। सारे हिमाचल में सिक्किम से लेकर के लदाख तक बौद्धिष्ठ हैं और इनकी लैग्वेज का हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं यह दरखास्त करता हूं कि यादि हम चाहते हैं तो इसको पॉलिटिक्स से बाहर निकालें, सीरियस होकर सरकार उर्दू के लिए और बाकी माझनारिटीज के लिए काम करें और सही रूप में करें। सिर्फ कमेटियां बना दें या 5-6 और कमीशन बना दें 5-6 कमेटीज बना दें, उसका भी खर्च शो करके एक साल के बादरिकमेंडेशन आएगी-क्या पचास साल में कमेटियों में ही रहना है? किसको नहीं पता कि उर्दू का क्या महत्व हैं, उर्दू को चाहने वाले कौन हैं? इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री चन्द्रकला पांडे (पश्चिम बंगाल) : माननीय उपसभापति महोदय, हम आज उर्दू भाषा के लिए यहां बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी भी हैं और गम भी कि बहुत देर से हम किसी भाषा, किसी जुबान पर यहां चर्चा करने के लिए आए हैं। यहां पर अपने 12 वर्ष के

समय में मुझे याद हैं कि बार हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, उर्दू पर बातचीत की थी और वह विश्वविद्यालय किस रूप में काम कर रहा है, यह खोज-खबर लेने के बाद पता चला है कि जिस रूप में हमने यहा सोचा था कि उन्नति करेगा, वैसे नहीं कर पाया। उर्दू जुबान की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि इसके साथ पूरी एक तहजीब जुड़ी हुई है और हम, जो हिन्दी पढ़ने-पढ़ने वाले लोग हैं, उनके साथ उर्दू का उतना ही संबंध है जितना यहां आपस में बैठे हुए जो सांसद हैं, उनका आपसी अतरंग संबंध है। हिन्दी और उर्दू का संबंध भी वैसा ही है। सर, मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूँगी। ऐसा न हो बहुत देर हो जाए हम भीर की शब्दावली में यह कहे कि

खत्म होने को जब आयी जिंदगी की दासतां,
उनकी फरमाइश हुई है, इसको दोबारा कहें।

ऐसा न हो कि सब कुछ खत्म हो जाए और बार-बार हम यह कहते रहे। सिद्धिकी साहब आज एक बहुत अच्छी बात यहां पर लेकर आए हैं। मैं जिस प्रदेश से आती हूं, पश्चिम बंगाल, वहां चाहे जिस भी कारण से ही, उर्दू के लिए हम लोग काफी काम करते हैं। हमारी उर्दू ऐकेडमी हैं। अखबार की बात हुई कि advertisements सरकारी नहीं मिलते हैं। हमारा “आबशार अखबार” है उसको सरकारी advertisements हिन्दी अखबारों से भी पहले मिलते हैं। एक और बात कहना चाहती हूं मदरसा बोर्ड बनाकर मदरसे का शिक्षा की आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ वहां जोड़ दिया गया हैं और स्कूल सर्विस कमीशन, कलिज सर्विस कमीशन को जो परीक्षाएं होती हैं उनमें उर्दू को उतनी ही प्रायेरिटी मिलती है जितनी हिन्दी को मिलती हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि बिहार मैं भी इस तरह मदरसा बोर्ड बनाकर ...

(व्यवधान) ..

श्री माननीय सदस्य : बिहार मैं हूं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे : उर्दू की शिक्षा का मुख्य धारा के साथ जोड़ दिया जाए। अगर नहीं हैं तो मुख्य शिक्षा के साथ जोड़कर उसकी बेहतरी के लिए भी उतना ही बात सोची जाए। अगर सब कुछ वहां हैं तो फिर आज जो बात उठी है, वह उठनी ही नहीं चाहिए थी। जगन्नाथ मिश्र जी ने जिस उर्दू यूनिवर्सिटी का बात की थी, मजहर-उल-हक, उसका प्रस्ताव अभी भी अगर कागज पर हैं तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि कब तक वह असलियत में उत्तर आएगा? एनसीपीएल का बजट अभी तक 11करोड़ है। करोड़ का बजट बहुत कम है। उर्दू की बेहतरी के लिए क्या इस बजट को और अधिक बढ़ाया जाएगा? गांवों में शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। मैं यह पूछना चाहूँगी कि कितने प्रतिशत शिक्षक मित्र हैंसियत से उर्दू के लिए नियुक्त किए गए हैं? उर्दू कंसलटेटिव बोर्ड बनाया गया था, जिसका काम था नीतियों का क्रियान्वयन करना,

[11 May, 2005]

RAJYA SABHA

लेकिन वह पूरी तरह सक्रिय नहीं हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, इसके चेयरमैन का पद भी अब तक खाली हैं। वह चेयरमैन का पद कब तक भर लिया जाएगा? अभी हमारे सांसद मित्र ने यह बताया कि देश की आजादी की लड़ाई से उर्दू का बहुत गहरा सादका था “इंकलाब शब्द उर्दू से ही हमने अपनाया। मैं अपनी ओर से यह कहना चाहूंगी कि हिन्दी भाषा बेहतरी के लिए जितना कुछ काम किया जा रहा है, अगर उसका पचास प्रतिशत भी उर्दू के लिए किया जाए तो उर्दू के लिए हमें यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। राजभाषा की दृष्टि से केवल हिन्दी को बढ़ावा दिया जाता है और भारतीय भाषाएं, केवल उर्दू ही नहीं, बहुत उपेक्षा की शिकार होती हैं। मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूंगी कि सभी भारतीय भाषाओं की बेहतरी के लिए एक कमेटी बनायी जाए और सबके लिए बजट आवंटित किया जाए। उर्दू वह जुबान है, जिसके बारे में हमारे शायरों ने लिखा :

वहीं वहीं इंसानियत हुई महसूस
जहां—जहां भी चले मेरी जुबां के लोग ।

जहां—जहां उर्दू जुबां के लोग हैं, इंसानियत वहां—वहां हमेशा महसूस की जाती रही हैं और महसूस की जाती रहेगी। मैं इन कुछ प्रश्नों और सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि हमें और इंतजार न करना पड़े। उर्दू की बेहतरी के लिए आप कुछ नयी योजना लेकर आइए।
धन्यवाद।

MESSAGES FROM LOK SABHA

The Bihar Value Added Tax Bill, 2005

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Bihar value Added Tax Bill, 2005, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 2005.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table of the House.